

E Learning Study Material

BY Prof YADWENDRA SINGH

MAHARAJA COLLEGE ARA

V K S UNIVERSITY ARA BIHAR

BA PART TWO ECONOMICS HONS

PAPER THIRD

Industrial Policy of 1991 of India

Economic Reforms in India mean the policies introduced since 1991 with a view to improve the levels of efficiency, productivity, profitability and competitiveness in the economy

With the gradual liberalisation of the 1956 Industrial Policy in the mid-eighties the tempo of industrial development started picking up. But the industry was still feeling the burden of many controls and regulations. For a faster growth of industry, it was necessary that even these impediments should be removed

सन् 1991 के जून माह में श्री नरसिम्हा राव सरकार के काल में जाने के पश्चात् 24 जुलाई 1991 को अपनी औद्योगिक नीति के

अन्तर्गत उद्योगों के उपायों के क्षेत्र की घोषणा की।

उद्देश्य:-

नई औद्योगिक नीति, 1991 उद्योग को लाइसेंस प्रणाली को बेड़ियों से मुक्त करने का प्रयास करती है, लाव्यनिक क्षेत्र की भूमिका को काफ़ी कम करती है और भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। नई औद्योगिक नीति मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

- (i) विनिर्माणक उपकरणों जैसे लाइसेंस और निर्यात से उद्योग को उधार बनाना
 - (ii) लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना
 - (iii) आम आदमी के लाभ के लिए उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना
 - (iv) व्यवसायिक तर्ज पर लाव्यनिक उद्यमों को चलाना और इस प्रकार उनके नुकसान को कम करना।
 - (v) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण और औद्योगिकता के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना
 - (vi) प्रतिस्पर्धा के लाभ तीव्र गति से औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- 1991 की नई औद्योगिक नीति ने चार मुख्य क्षेत्रों अर्थात् लाव्यनिक क्षेत्र की औद्योगिक लाइसेंसिंग भूमिका, विदेशी निवेश और औद्योगिकी और एमआरटीपी (MRTP) अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।